[2024] 10 एससीआर 425: 2024 आईएनएससी 757

बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

बनाम।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 11005/2024)

04 अक्टूबर 2024

[बेला एम. त्रिवेदी* और सतीश चंद्र शर्मा, जे.जे.]

विचार के लिए मुद्दा

मुद्दा यह उठा कि क्या प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 8-कंपनी की तकनीकी बोली को स्वीकार करते हुए, और इसे सफल बोलीदाता घोषित करते हुए, हालांकि प्रतिवादी नंबर 8 ने निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस-एनआईटी के खंड 10 में निहित योग्यता मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया था।

हेडनोट्स

सरकारी अनुबंध - न्यायिक हस्तक्षेप - का दायरा - मेगा परियोजना के लिए निविदा - प्रतिवादी संख्या 1-बीसीसीएल, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने निविदा जारी की - अपीलकर्ता ने निविदा में भाग लिया, हालांकि, इस आधार पर तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया कि उसने एनआईटी के खंड 10 का अनुपालन नहीं किया, बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में - प्रतिवादी नंबर 8 कंपनी सफल बोलीदाता घोषित - व्यथित, अपीलकर्ता ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की कि प्रतिवादी नंबर 8 ने निविदा दस्तावेजों को जमा करते / अपलोड करते समय वित्तीय क्षमता के संबंध में खंड 10 एनआईटी के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं और यह केवल तब था जब दस्तावेजों की कमी के बारे में प्रतिवादी नंबर 8 से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तकनीकी बोलियों के खुलने के

---

* Author

बाद प्रस्तुत की गई थी - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, प्रतिवादी की तकनीकी बोली को खारिज करते हुए अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी नंबर 8 की तकनीकी बोली को स्वीकार करते हुए - चुनौती दी:

आयोजित: सरकारी निकायों/साधनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी तरह से निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से कार्य करें, विशेष रूप से मेगा परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्रदान करने में - मनमानेपन या भेदभाव के किसी भी तत्व से पूरी परियोजना में बाधा उत्पन्न हो सकती है जो सार्वजनिक हित में नहीं होगी - न्यायालय अनुबंध प्रदान करने के मामले में अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और यह केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था; और यह कि सरकार और उसके तंत्रों को संविदाओं में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए - हालांकि, सरकार/साधनों का निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए और किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए या दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए - अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानेपन से घृणा करता है - सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होता है कि बोली प्रक्रिया के दौरान कोई पूर्वाग्रह, पक्षपात या मनमानापन नहीं दिखाया जाता है और यह कि पूरी बोली प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाती है- तथ्यों पर, अटॉर्नी की शक्ति को दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ता, प्राप्तकर्ता के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया था, और प्रतिवादी द्वारा निर्धारित प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, अपीलकर्ता द्वारा एनआईटी के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने से पहले विधिवत उत्पन्न नहीं हुआ था - इसलिए, अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या न्यायसंगत आधार नहीं - अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को बिल्कुल बाहरी आधार पर खारिज करने और प्रतिवादी नंबर 8 की तकनीकी बोली को स्वीकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई, हालांकि खंड 10 एनआईटी की अनिवार्य आवश्यकता का पूरी तरह से अनुपालन न करते हुए, और बाद में बोली लगाने वालों की तकनीकी बोलियों के खुलने के बाद दस्तावेजों की कमी को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी नंबर 8 को बुलाना, पूरी तरह से मनमाना और अवैध - इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजना है और मेगा परियोजनाओं में से एक है, यह न्यायालय विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि प्रतिवादी और प्रतिवादी नंबर 8 के

विशेष प्रयोजन वाहन के बीच पहले ही समझौता किया जा चुका है - अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज करने और प्रतिवादी नंबर 8 को सफल बोलीदाता घोषित करने का प्रतिवादी का आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से मनमाना है, इस प्रकार, अनुच्छेद 14 के अवैध, भेदभावपूर्ण और उल्लंघन को रद्द कर दिया जाता है - उक्त निर्णय के अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई/प्रक्रिया या समझौता भी रद्द कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 19-21, 29, 30]

केस लॉ का हवाला

स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एम एंड एन प्रकाशन लिमिटेड और अन्य [1993] 1 एससीआर 81: **(1993) 1 एससीसी 445**; टाटा सेल्युलर बनाम. भारत संघ [1994] आपूर्ति 2 एससीआर 122: (1994) 6 एससीसी 651; एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2004) 3 एससीसी 553; जगदीश मंडल बनाम. उड़ीसा राज्य और अन्य [2006] आपूर्ति 10 एससीआर 606: (2007) 14 एससीसी 517; मिहान इंडिया लिमिटेड बनाम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य [2022] 19 एससीआर 523: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 574; सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य [2016] 4 एससीआर 890: (2016) 8 एससीसी 622 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

मुख्तारनामा अधिनियम, 1882

कीवर्ड की सूची

निविदा; तकनीकी बोली; सफल बोलीदाता; पात्रता मानदंड; सरकारी अनुबंध; न्यायिक हस्तक्षेप; मेगा परियोजना के लिए निविदा; तकनीकी रूप से अयोग्य; लेखा परीक्षित बैलेंस शीट; निविदा दस्तावेज जमा करना/अपलोड करना; तकनीकी बोली समिति; सरकारी निकाय/उपकरण; मेगा परियोजनाओं के लिए ठेके देना; मनमानेपन, पूर्वाग्रह से मुक्त या दुर्भावना से मुक्त; सरकारी निकाय; सार्वजनिक प्राधिकरण; संविदात्मक मामले; समानता

का अधिकार; बोली प्रक्रिया; वित्तीय क्षमता; लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट; पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी; तकनीकी बोलियों को खोलना। **मामला उत्पन्न होने से**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 11005 की सिविल अपील संख्या 2024

2024 की डब्ल्यूपीसी संख्या 2896 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.07.2024 से

पार्टियों में उपस्थिति

रविशंकर प्रसाद, नवनीति सिंह, सीनियर एडवोकेट, पंकज भगत, एडवोकेट।
अपीलकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी., बलबीर सिंह, अनुपम लाल दास, सीनियर एडवोकेट, अंकुर कश्यप, अमित शर्मा, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

त्रिवेदी, जे.

1. याचिका मंजूर

2. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने में न्यायसंगत था, जबकि प्रतिवादी नंबर 8-कंपनी की तकनीकी बोली को स्वीकार करते हुए, और इसे सफल बोलीदाता घोषित करते हुए, हालांकि प्रतिवादी नंबर 8 ने क्लॉज 10 में निहित योग्यता मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया था दिनांक 16.08.2023 को निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) का, और इस तरह उसमें निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा था?

3. अपीलकर्ता-बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2896 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक

18.07.2024 पर हमला किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज करने वाले प्रतिवादी-बीसीसीएल की तकनीकी बोली समिति के दिनांक 06.05.2024 के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की गई है।

4. प्रतिवादी संख्या 1-बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और प्रतिवादी संख्या 2-7 बीसीसीएल के अधिकारी/कर्मचारी हैं। 16.08.2023 को प्रतिवादी नंबर 1 ने एक निविदा असर संदर्भ संख्या जारी की। एनआईटी नं. (ख) मैसर्स बीसीसीएल/सीएमसी/एमडीओ-आरएस/सिमलाबहाल/बस्ताकोला क्षेत्र/2023/318 को पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर अमलगमेटेड ईस्ट भुग्गाडीह शिमला कोयला खान से कोयले के निष्कर्षण और बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र में प्राधिकरण को उसकी सुपुर्दगी के लिए पुन खोलने, बचाने, पुनर्वास, विकास, निर्माण और प्रचालन करने की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अपीलकर्ता-कंपनी ने बोर्ड के संकल्प दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से उक्त निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अपनी निदेशक लालती देवी को अधिकृत करने का संकल्प लिया और उनके पक्ष में निर्धारित प्रारूप में पावर ऑफ अटॉर्नी भी निष्पादित की। उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को 14.11.2023 को नोटरीकृत किया गया था। तदनुसार, अपीलकर्ता ने 29.11.2023 को अपनी बोली प्रस्तुत करके उक्त निविदा में भाग लिया।

5. उक्त निविदा की तकनीकी बोलियां 04.12.2023 को खोली गईं और उसी के मूल्यांकन के बाद, अपीलकर्ता को 06.05.2024 को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दिनांक 07.05.2024 की निविदा सारांश रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने एनआईटी (भाग I/कवर I अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज (OID) बिंदु संख्या 02 परिशिष्ट II (बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी) के खंड 10 का अनुपालन नहीं किया था।

6. तकनीकी रूप से योग्य दो बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां 07.05.2024 को खोली गईं और प्रतिवादी संख्या 8-कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-बीसीसीएल के उक्त निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया है।

7. 23.08.2024 को न्यायालय ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए थे और कैविएट पर उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने मौखिक रूप से न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वे विचाराधीन परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। बीसीसीएल की निविदा सिफारिश समिति द्वारा 06.05.2024 को लिए गए निर्णय पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए, हमने दिनांक 17.09.2024 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक पूरी निविदा कार्यवाही के संबंध में मूल फाइल मांगी थी और इसे हमारे अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुति: -

8. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का कारण घोर मनमाना और भेदभावपूर्ण था क्योंकि न केवल प्रतिवादी नंबर 8 की बोली को स्वीकार किया गया था, हालांकि यह महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ नहीं था, लेकिन पात्रता की कमी को पूरा करने के लिए बाद में उक्त दस्तावेजों को दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने एनआईटी की सभी शर्तों का पालन किया था, हालांकि अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को प्रतिवादी-बीसीसीआई की तकनीकी बोली समिति द्वारा बाहरी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बोली दस्तावेजों पर 13.11.2023 को हस्ताक्षर किए गए थे, और पावर ऑफ अटॉर्नी सहित अन्य दस्तावेजों को 14.11.2023 को नोटरीकृत किया गया था। उनके अनुसार बोली दस्तावेज 29.11.2023 को यानी निर्धारित समय के भीतर अपलोड/दाखिल किए गए थे, जिसमें एनआईटी के खंड 10 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था। श्री प्रसाद ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा है कि सरकार और उसके तंत्र के निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनेसबरी सिद्धांत के आवेदन द्वारा परखा जाना चाहिए, बल्कि मनमानेपन से भी मुक्त होना चाहिए। सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत का आह्वान करते हुए, श्री प्रसाद ने अंत में प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की बोली प्रतिवादी बीसीसीएल के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी और अनुकूल (लगभग 700 करोड़ रुपये) थी, और प्रतिवादी नंबर 8 को निविदा आवंटित करके, जो अन्यथा भी अयोग्य था, प्रतिवादी बीसीसीएल के माध्यम से जनता को एक समान नुकसान हुआ।

9. हालांकि, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनुपम लाल दास और श्री विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी प्रतिवादी नंबर 1 से 7 के लिए उपस्थित

होकर अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज करने वाले निविदा मूल्यांकन समिति के निर्णय को सही ठहराते हुए, प्रस्तुत किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 07.11.2023 थी, जिसे 14.11.2023 को नोटरीकृत किया गया था, जबकि अनिवार्य बोली दस्तावेजों को 13.11.2023 को निष्पादित किया गया था, जो एनआईटी के खंड 10 भाग I/कवर 1 (ओआईडी) के अनुरूप नहीं था। उनके अनुसार, अनिवार्य बोली दस्तावेजों को 13.11.2023 को निष्पादित किया गया था, जब निष्पादक के पास उक्त बोली दस्तावेजों को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम उस तारीख को अपने पक्ष में एक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी होना आवश्यक था, जिस पर वह हस्ताक्षर कर रहा था और बोली दस्तावेजों को निष्पादित कर रहा था, और इसलिए अपीलकर्ता एनआईटी की शर्तों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन के दौरान प्रतिवादी बीसीसीएल बोलीदाताओं से कमी के दस्तावेज मांग सकता है, लेकिन उन्हें बोली दस्तावेजों को बदलने की अनुमति नहीं दे सकता है। जहां तक प्रतिवादी नंबर 8-कंपनी का संबंध था, निविदा समिति ने लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में 09.04.2024 को स्पष्टीकरण मांगा था, जो समिति का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली अन्य बोलीदाताओं के अनुरूप थी, जो प्रतिवादी संख्या 8 के समान स्थित थे। विद्वान वकीलों ने यह भी प्रस्तुत किया कि स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजना और राष्ट्रीय महत्व की है, और अनुबंध प्रदान करने के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है, न्यायालय इसके साथ इंटरफेस नहीं कर सकता है, भले ही न्यायालय को पता चले कि कुल मनमानी थी या निविदा दुर्भावनापूर्ण तरीके से दी गई थी। विद्वान. वकीलों ने अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए निर्णयों की श्रेणी पर भरोसा किया है, जिसे इसके बाद आवश्यक हो सकता है।

10. प्रतिवादी नंबर 8 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बलबीर सिंह ने प्रतिवादी नंबर 1 से 7 की ओर से की गई प्रस्तुतियों को अपनाते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 8 को 10.06.2024 को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1- बीसीसीएल और मैसर्स शिमला कोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 8-कंपनी द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन) ने भी 27.06.2024 को कोयला खनन समझौता किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा अपील में

उठाए गए दुर्भावना की कोई दलील नहीं थी और तय कानूनी स्थिति के अनुसार, न्यायालयों को अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्कैन करते समय वृहत्प्रदर्शक शीशा का उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि छोटी गलती एक बड़ी गलती की तरह दिखाई दे।

विश्लेषण:-

11. अभिलेखों और दस्तावेजों से और पार्टियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों से स्पष्ट रूप से निर्विवाद तथ्य यह है कि विचाराधीन परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस प्रतिवादी बीसीसीएल द्वारा 16.08.2023 को जारी किया गया था, जिसके जवाब में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 8 ने अपने संबंधित बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अपीलकर्ता कंपनी ने दिनांक 07.11.2023 के बोर्ड संकल्प के माध्यम से अपनी निदेशक लालती देवी को निविदा में भाग लेने के उद्देश्य से अधिकृत किया था और उनके पक्ष में दिनांक 07.11.2023 को पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई थी। उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को 14.11.2023 को नोटरी के समक्ष नोटरी किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता ने 29.11.2023 को बोली दस्तावेज प्रस्तुत/अपलोड किए, जो जमा करने की अंतिम तिथि 01.12.2023 से पहले है। यह भी विवादित नहीं है कि तकनीकी बोलियां 04.12.2023 को खोली गईं और अपीलकर्ता को 06.05.2024 को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। निविदा सारांश रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 के उद्धरण में कॉलम 'टिप्पणी' में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 'एनआईटी के खंड संख्या 10 (भाग I/कवर I, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज (OID) बिंदु संख्या 02 परिशिष्ट II (बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी) का अनुपालन नहीं किया।

12. यह भी विवादित नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 8 ने निविदा दस्तावेजों को जमा करते / अपलोड करते समय वित्तीय क्षमता के संबंध में एनआईटी के खंड 10 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं और यह केवल तब था जब दस्तावेजों की कमी के बारे में प्रतिवादी नंबर 8 से स्पष्टीकरण मांगा गया था, उक्त लेखापरीक्षित बैलेंस शीट 17.04.2024 को तकनीकी बोलियां 04.12.2023 को खोले जाने के बाद जमा की गई थी। यह और विवादित नहीं

है कि पात्र दो तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां 07.05.2024 को खोली गईं और प्रतिवादी नंबर 8 कंपनी को सफल बोलीदाता पाया गया।

13. वर्तमान मामले में पूरा विवाद एनआईटी दिनांक 16.08.2023 के खंड 10 की व्याख्या के आसपास केंद्रित है, इसलिए इसे सुविधा के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाता है।

> "**10**. वित्तीय क्षमता को प्रमाणित करने के लिए, बोलीदाताओं को निम्नलिखित जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:
>
> (क) नेट वर्थ का मूल्य (भारतीय रुपये में और आरएफबी के परिशिष्ट I के अनुलग्नक III में प्रदान किए गए प्रारूप में);
>
> (ख) पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में कुल आय का मूल्य जैसा कि बोलीदाता द्वारा चुना गया है (भारतीय रुपये में और आरएफबी के परिशिष्ट I के अनुलग्नक III में प्रदान किए गए प्रारूप में);
>
> (ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या, जहां लागू हो; और
>
> (घ) वित्तीय क्षमता के संबंध में एनआईटी के पैरा 10 में यथा विनिदष्ट दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां।
>
> **नोट**: यदि बोलीदाता एक संघ है, तो उपरोक्त प्रमाण पत्र और जानकारी सभी सदस्यों के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी और संघ की वित्तीय क्षमता का आकलन इस प्रकार प्रस्तुत की गई जानकारी को जोड़कर किया जाएगा।
>
> बोलीदाता अपलोड किए गए दस्तावेजों द्वारा पुष्टि किए गए वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज, जिसके आधार पर ऑटो मूल्यांकन होता है, केवल विचार किया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करता है, तो उसे कोई संज्ञान नहीं दिया जाएगा।

£ चार्टर्ड एकाउंटेंट के लगभग समकक्ष कोई भी व्यक्ति इस आरएफबी के तहत आवश्यक प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है। जिन क्षेत्राधिकारों के पास स्वयं का वर्णन करने या चार्टर्ड एकाउंटेंट (या किसी अनुमानित समकक्ष) के रूप में अभ्यास करने के लिए लेखाकारों के लिए लाइसेंस / प्रमाणन / सदस्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई भी योग्य लेखाकार इस आरएफबी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है।

बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करते समय दी गई जानकारी/घोषणा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी

क्रम सं.	योग्यता मानदंड से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना	प्रत्येक योग्यता मानदंड (पुष्टिकरण दस्तावेज) के खिलाफ बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी/घोषणा के समर्थन में बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (स्व-प्रमाणित और नोटरीकृत / ® प्रमाणित)
1	बोलीदाता का कवरिंग पत्र और बोली की स्वीकृति की शर्तें	बोलीदाता के कवरिंग लेटर की प्रति, बोली की शर्तों की स्वीकृति और बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रोफार्मा (आरएफबी के परिशिष्ट I में दिए गए) के अनुसार प्रतिबद्धताएं। **नोट:** यदि बोलीदाता एक संघ है, तो उपरोक्त दस्तावेजों पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2	वित्तीय क्षमता	i) बोलीदाता द्वारा चुने गए 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में से अंतिम वित्तीय वर्ष के अंत में बोलीदाता के नेटवर्थ मूल्य

® विदेश में निष्पादित और जारी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध भी किया जाना चाहिए और उस क्षेत्राधिकार में नोटरीकृत किया जाना चाहिए जहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। हालाँकि, हेग कन्वेंशन, 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं/सदस्यों द्वारा प्रदान की गई पावर ऑफ अटॉर्नी को भारतीय दूतावास द्वारा वैध करने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसके पास अनुरूप एपोस्टिल प्रमाणपत्र है।

∞ ऐसे क्षेत्राधिकारों में जहां वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं हैं, बोलीदाता के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षण करने वाली लेखा परीक्षकों की फर्म इस आरएफबी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।

		को निर्दिष्ट करने वाला यूडीआईएन नंबर वाला प्रमाण पत्र, वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रदर्शित करता है और पुष्टि करता है कि निवल मूल्य की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुरूप है; ii) कुल आय की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति को भी निर्दिष्ट करता है;ii) बोलीदाता द्वारा चुने गए 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता की औसत कुल आय को निर्दिष्ट करने वाला यूडीआईएन नंबर वाला प्रमाण पत्र, वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रदर्शित करता है और औसत iii) बोलीदाता द्वारा चुने गए पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के लिए बोलीदाता की लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें बोलीदाता की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते शामिल हैं। iv) अनुलग्नक III में विधिवत भरा गया (आरएफबी के परिशिष्ट I में प्रदान किया गया)।

		नोट: I वित्तीय क्षमता के उद्देश्य से, बोलीदाता बोलियों के आमंत्रण की तिथि तक 4 (चार) तुरंत पूरे हुए लगातार वित्तीय वर्षों में से कोई भी 3 (तीन) वित्तीय वर्ष चुन सकता है। हालाँकि, बोलीदाता द्वारा चुने गए 3 (तीन) वित्तीय वर्ष प्रत्येक सदस्य (संघ के मामले में) और सहयोगी (एसोसिएट) के लिए समान होंगे, जिनकी वित्तीय क्षमता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई है और उस पर भरोसा किया गया है। ii. यदि बोलीदाता एक संघ है, तो उपरोक्त दस्तावेज सभी सदस्यों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने हैं। iii बोलीदाता उन सहयोगियों की नेट वर्थ संपत्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिनकी तकनीकी क्षमता और/या वित्तीय क्षमता प्रस्तुत की गई है और जिस पर भरोसा किया गया है।
3.	सत्यनिष्ठा संधि	आरएफबी के परिशिष्ट VIII में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित और साक्षी सत्यनिष्ठा समझौता। **नोट: यदि बोलीदाता एक संघ है, तो सत्यनिष्ठा समझौते पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।**
4.	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के लिए प्राधिकरण ("DSC")	क) यदि बोलीदाता स्वयं डीएससी धारक है और ऑनलाइन बोली लगा रहा है, तो

		बोलीदाता द्वारा इस आशय की स्व-घोषणा; या ख) यदि डीएससी धारक बोलीदाता की ओर से ऑनलाइन बोली लगा रहा है, तो बोलीदाता द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी, बोलीदाता की ओर से बोली प्रस्तुत करने के लिए डीएससी धारक को दी गई प्राधिकरण को प्रमाणित करती है।
5.	प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अन्य प्रतिबद्धताओं के समर्थन में वचनबद्धता	बोलीदाता को इस एनआईटी के संलग्नक I में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक वचन देना होगा, जिसमें ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी की वास्तविकता, अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति की प्रामाणिकता और ऐसी अन्य घोषणाएं शामिल होंगी। नोट: यदि बोलीदाता एक संघ है, तो वचन पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। (मूल वचन एनआईटी के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा)
6.	बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत योग्यता संबंधी जानकारी का समर्थन करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज़।	
नोट: प्रत्येक योग्यता मानदंड के विरुद्ध केवल एक फ़ाइल .pdf प्रारूप में अपलोड की जा सकती है। बोलीदाता द्वारा योग्यता मानदंड के विरुद्ध ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी/घोषणा का समर्थन करने के लिए कोई भी अतिरिक्त/अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ भी बोलीदाता द्वारा संबंधित योग्यता मानदंड के विरुद्ध अपलोड की जाने वाली उसी फ़ाइल (.pdf प्रारूप में) में जोड़े जा सकते हैं।		

भाग-1/कवर-1-अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज (“ओआईडी”)

क्रम सं.	योग्यता मानदंड से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना	प्रत्येक योग्यता मानदंड (पुष्टिकरण दस्तावेज) के खिलाफ बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी/घोषणा के समर्थन में बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (स्व-प्रमाणित और नोटरीकृत / प्रमाणित)
1.	बोलीदाता की कानूनी स्थिति	उपयुक्त होने पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़: 1. बोलीदाता की स्वामित्व/व्यक्तिगत स्थिति को साबित करने के लिए शपथ पत्र या कोई अन्य दस्तावेज़ (केवल तभी लागू होता है जब बोलीदाता एक व्यक्ति या एकमात्र स्वामी हो); 2. भागीदारी विलेख/समझौता जिसमें भागीदारों का नाम और निगमन का प्रमाण पत्र हो (केवल तभी लागू होता है जब बोलीदाता एक साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी हो); 3. बोलीदाता के नाम या किसी समान चार्टर/संवैधानिक दस्तावेज़ों वाले निगमन के प्रमाण पत्र के साथ एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख (जहां बोलीदाता एक कंपनी है वहां लागू); 4. ऊपर उल्लिखित किसी अन्य बोलीदाता के लिए लागू उपयुक्त दस्तावेज़। 5. अनुलग्नक I (आरएफबी का परिशिष्ट I) विधिवत भरा हुआ और अपलोड किया गया 6. संघ के मामले में: (i) उपरोक्त 1/2/3 (जैसा लागू हो) के अनुसार सभी सदस्यों का विवरण, (ii) आरएफबी के परिशिष्ट IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार संयुक्त बोली समझौता: (iii) अनुलग्नक I (आरएफबी का परिशिष्ट I) विधिवत भरा हुआ और अपलोड किया गया;

		(iv) अनुलग्नक IV (आरएफबी का परिशिष्ट I) विधिवत भरा और अपलोड किया गया 7. बोलीदाता/सदस्यों के अंतिम लाभकारी स्वामित्व के संबंध में संलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में एक वचनबद्धता, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रकाश में, दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 6/18/2019-पीपीडी के साथ पठित, समेकित एफडीआई नीति (15 अक्टूबर 2020 से प्रभावी) और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (एफडीआई नीति अनुभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 17 अप्रैल 2020 के प्रेस नोट संख्या 3 (2020 श्रृंखला), जिनमें से प्रत्येक को समय-समय पर संशोधित या पूरक किया गया है। 8. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2.	वित्तीय क्षमता	परिशिष्ट II (जैसा लागू हो) और परिशिष्ट III (यदि बोलीदाता एक संघ है) के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार
3.	इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए अधिदेश फॉर्म	इस एनआईटी के अनुलग्नक II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार विधिवत भरे गए अधिदेश फॉर्म की प्रति
4.	**बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत योग्यता संबंधी जानकारी का समर्थन करने वाला कोई अन्य दस्तावेज़।**	

14. यह नोट करना प्रासंगिक है कि एनआईटी के साथ संलग्न बोली के लिए अनुरोध (आरएफबी) में उसकी धारा II में "बोलीदाताओं को अनुदेश" निहित हैं। उक्त अनुदेशों के खंड 216 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी बोली अनुदेश का अनुपालन न करने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उसके खंड 225 में विशेष रूप से कहा गया है कि बोलीदाता एनआईटी के पैरा 9 और पैरा 10 में सूचीबद्ध अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

15. उपर्युक्त खंड 10 के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बोलीदाताओं को विशेष रूप से अपनी वित्तीय क्षमता को प्रमाणित करने के लिए योग्यता मानदंडों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी और स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। वित्तीय क्षमता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से, बोलीदाताओं को बोलीदाता द्वारा चुने गए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्टों की स्कैन की गई प्रतियां (स्व-प्रमाणित और नोटरीकृत/प्रमाणित) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें बोलीदाता के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे शामिल थे, जिसमें अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेज शामिल थे। यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अनिवार्य अपेक्षा थी, यह अर्हता मानदंड से संबंधित होने के साथ-साथ आरएफबी के खंड 225 से भी संबंधित थी।

16. बेशक, प्रतिवादी नंबर 8 ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रतियां जमा नहीं की थीं, बोली दस्तावेजों को जमा करने/अपलोड करने के समय, निर्धारित अंतिम तिथि यानी 01.12.2023 से पहले और इसे 17.04.2024 को केवल तभी प्रस्तुत किया गया था जब 04.12.2023 को तकनीकी बोलियां खोले जाने के बाद प्रतिवादी नंबर 8 से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

17. जब अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को उत्तरदाताओं द्वारा 06.05.2024 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह एनआईटी के खंड 10 अर्थात् भाग I/कवर I अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज (OID) बिंदु संख्या 02 परिशिष्ट II (बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी) का अनुपालन नहीं करता है, तो प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से प्रतिवादी संख्या 8 की तकनीकी बोली को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था, जो स्पष्ट रूप से एनआईटी के समान अनिवार्य खंड 10 के अनुपालन में नहीं था। प्रतिवादी बीसीसीएल इस बात को सही ठहराने में बुरी तरह विफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 8 की तकनीकी बोली को कैसे स्वीकार किया गया था जब उसने एनआईटी के खंड 10 में उल्लिखित योग्यता मानदंडों से संबंधित अपेक्षित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

18. प्रतिवादी बीसीसीएल की ओर से एक झूठा सबमिशन किया गया था कि निविदा मूल्यांकन समिति दस्तावेजों की कमी के लिए कॉल कर सकती है और दस्तावेजों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दे सकती है, और प्रतिवादी नंबर 8 को केवल कमी दस्तावेज जमा

करने के लिए कहा गया था। हम न तो प्रभावित हैं और न ही उक्त प्रस्तुतियों को स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, इस तथ्य के अलावा कि प्रतिवादी संख्या 8 की तकनीकी बोली एनआईटी के खंड 10 का अनुपालन न करने के लिए सीमा पर खारिज किए जाने के योग्य थी, अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का कोई कानूनी और न्यायसंगत कारण भी नहीं था। बेशक, जब अपीलकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, तो अपीलकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए संबंधित हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी को विधिवत नोटरीकृत किया गया था। केवल इसलिए कि बोली दस्तावेजों पर 13.11.2023 को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुश्री लालती देवी द्वारा 07.11.2023 को उनके पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को 14.11.2023 को नोटरीकृत किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलकर्ता कंपनी के उक्त प्रतिनिधि के पास उस दिन दस्तावेज जमा करने का अपेक्षित अधिकार नहीं था जिस दिन बोली दस्तावेज जमा किए गए थे, न ही यह कहा जा सकता है कि एनआईटी के खंड 10 की अनिवार्य आवश्यकता का कोई गैर-अनुपालन था जैसा कि प्रतिवादी बीसीसीएल द्वारा पेश किया जाना था। एनआईटी में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी किया जाना था। एनआईटी के खंड 10 के भाग-1/कवर I के अनुसार, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित, केवल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (स्व-प्रमाणित और नोटरीकरण/प्रमाणित) प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिन्हें बोलीदाता द्वारा प्रत्येक मानदंड के खिलाफ ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी/घोषणा के समर्थन में बोलीदाता द्वारा अपलोड किया जाना था, और पावर ऑफ अटॉर्नी के मानदंडों के खिलाफ, यह कहा गया था कि यह संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रारूप के अनुसार थी और 14.11.2023 को विधिवत नोटरीकृत की गई थी, और नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किए गए थे।

19. यह नोट करना उचित होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, 1882 की धारा 2 के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी का प्राप्तकर्ता, यदि वह ठीक समझता है, तो अपने नाम और हस्ताक्षर के साथ किसी भी उपकरण या चीज को निष्पादित या कर सकता है, और अपनी खुद

की मुहर, जहां सीलिंग की आवश्यकता होती है, शक्ति के दाता के अधिकार से; और प्रत्येक उपकरण और चीज जिसे इस प्रकार निष्पादित और किया गया है, कानून में उतना ही प्रभावी होगा जितना कि इसे नाम में शक्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा निष्पादित या किया गया था, और उसके दाता के हस्ताक्षर और मुहर के साथ। वर्तमान मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी को दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ता, प्राप्तकर्ता के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया था, और प्रतिवादी बीसीसीएल द्वारा निर्धारित प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, अपीलकर्ता द्वारा एनआईटी के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ इसे प्रस्तुत करने से पहले विधिवत नोटरीकृत किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या न्यायसंगत आधार नहीं था।

20. इस प्रकार, अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को बिल्कुल बाहरी आधार पर खारिज करने और प्रतिवादी नंबर 8 की तकनीकी बोली को स्वीकार करने में प्रतिवादी बीसीसीएल की उक्त कार्रवाई, हालांकि एनआईटी के खंड 10 की अनिवार्य आवश्यकता के पूरी तरह से गैर-अनुपालन में प्रस्तुत की गई, और बाद में बोली लगाने वालों की तकनीकी बोलियों के खुलने के बाद दस्तावेजों की कमी को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी नंबर 8 को बुलाया, पूरी तरह से मनमाना और अवैध था।

21. इस न्यायालय के निर्णयों की श्रेणी में प्रतिपादित कानूनी प्रस्ताव के प्रति कोई असहमति नहीं हो सकती है, जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों ने इस आशय का भरोसा किया है कि न्यायालय अनुबंध प्रदान करने के मामले में अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और यह केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था; और यह कि सरकार और उसके तंत्र को अनुबंधों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि सरकार/उसके तंत्र का निर्णय मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए और किसी भी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए या दुर्भावनापूर्ण द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते सरकारी निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविदात्मक मामलों से निपटने के दौरान भी निष्पक्षता, समानता और सार्वजनिक हित को बनाए रखें। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानेपन से घृणा करता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का पक्षपात या

मनमानी नहीं की जाती है और पूरी बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाती है।

22. इस मोड़ पर, हम सरकारी अनुबंधों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं।

23. **स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड और अन्य,** इस न्यायालय ने अनुबंधों के पुरस्कार की न्यायिक समीक्षा के दायरे से निपटने के दौरान: -

> "18. राज्य की ओर से दर्ज की गई संविदाओं के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि क्या "निर्णय लेने की प्रक्रिया" में कोई दुर्बलता रही है। इस संबंध में **नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल बनाम भारत संघ के मामले का संदर्भ दिया जा** सकता है। इवांस [(1982) 3 ऑल ईआर 141] जहां यह कहा गया था कि: (पृष्ठ 144 ए) 1 [1993] 1 एससीआर 81: (1993) 1 एससीसी 445 440
>
> "न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को उचित उपचार प्राप्त हो, न कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण, निष्पक्ष उपचार प्रदान करने के बाद, किसी ऐसे मामले पर पहुंचता है जिसे वह अधिकृत करता है या कानून द्वारा खुद के लिए एक निष्कर्ष तय करने के लिए अधिकृत है जो अदालत की नजर में सही है।"
>
> न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अदालत अनुबंध की शर्तों के विवरण की जांच नहीं कर सकती है जो सार्वजनिक निकायों या राज्य द्वारा दर्ज की गई हैं। ऐसी किसी भी जांच के दायरे पर न्यायालयों की अंतर्निहित सीमाएं हैं। लेकिन उसी समय जैसा कि पूर्वोक्त मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कहा गया था, नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल वी। इवांस [(1982) 3 ऑल ईआर 141] अदालतें निश्चित रूप से जांच कर सकती हैं कि क्या "निर्णय लेने की प्रक्रिया" उचित, तर्कसंगत, मनमानी नहीं थी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती थी।

24. **टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ** में इस न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए थे।

"94. उपरोक्त से निकाले गए सिद्धांत हैं:

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था।

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं दोषपूर्ण हो सकता है।

(4) निविदा के आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा का आमंत्रण संविदा के दायरे में है। सामान्यतया, निविदा स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अधिक बार नहीं, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक सहवर्ती है। हालांकि, निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनेसबरी सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के आवेदन द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि मनमानी से मुक्त होना चाहिए जो पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए या दुर्भावनापूर्ण द्वारा सक्रिय नहीं होना चाहिए।

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और व्यय में वृद्धि हो सकती है।

इन सिद्धांतों के आधार पर हम इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे क्योंकि वे हमें सही सिद्धांतों के रूप में बताते हैं।

---

2 [1994] Supp. 2 SCR 122 : (1994) 6 SCC 651

25. यह **एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य**[3], में भी आयोजित किया गया है: -

> "53. उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि जब राज्य का कोई साधन अपने संविदात्मक, संवैधानिक या वैधानिक दायित्वों में अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित रूप से सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य करता है, तो यह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 14 में पाए गए संवैधानिक गारंटी के विपरीत कार्य करता है।

26. **जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा**[4] **राज्य और अन्य**, इस न्यायालय ने कई निर्णयों पर चर्चा करने के बाद निविदा मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा निर्धारित करने के लिए दो परीक्षण निर्धारित किए। वे हैं: -

> "22. (i) क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी के पक्ष में आशयित है;
>
> नहीं तो
>
> क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी को लाभ पहुंचाने के इरादे से किया गया है
>
> या
>
> क्या अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि अदालत कह सकती है: "यह निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उचित तरीके से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य करते हुए इस पर नहीं पहुंच सकता था
>
> (ii) क्या जनहित प्रभावित होता है।
>
> यदि उत्तर नकारात्मक हैं तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी निविदाकर्ता/ठेकेदार या राज्य की उदारता के वितरण (स्थलों/दुकानों का आवंटन, लाइसेंस, डीलरशिप और फ्रेंचाइजी का अनुदान) को काली सूची में डालने या दंडात्मक परिणाम लागू करने से जुड़े मामले अलग

---

3 2004) 3 SCC 553

4 [2006] Supp. 10 SCR 606 : (2007) 14 SCC 517

स्तर पर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता हो सकती है।

27. **मिहान इंडिया लिमिटेड बनाम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य**[5], यह देखते हुए कि सरकारी निकायों द्वारा दिए गए सरकारी अनुबंधों को संविदात्मक मामलों से निपटने के दौरान निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन को बनाए रखना चाहिए, पैरा 50 में निम्नानुसार देखा गया था: -

> "50. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सरकारी अनुबंधों में, यदि सरकारी निकायों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि अनुबंध संबंधी मामलों से निपटने के दौरान निष्पक्षता, समानता और कानून का शासन बनाए रखा जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानेपन से घृणा करता है। पारदर्शी बोली प्रक्रिया न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के पक्ष में है कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। यह कहा जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी राज्य से निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने की मांग करती है जब तक कि जनहित अन्यथा न हो। यह उचित है कि किसी भी निजी वैध हित के समझौते की डिग्री सार्वजनिक हित के समानुपातिक रूप से मेल खानी चाहिए यह उचित है कि किसी भी निजी वैध हित के समझौते की डिग्री सार्वजनिक हित के समानुपातिक रूप से मेल खानी चाहिए यह उचित है कि किसी भी निजी वैध हित के समझौते की डिग्री सार्वजनिक हित के समानुपातिक रूप से मेल खानी चाहिए

28. **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य**[6]**,** में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि एनआईटी की अवधि आवश्यक है या नहीं, नियुक्तिकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय है जिसका सम्मान किया

---

5 [2022] 19 SCR 523 : (2022) SCC Online SC 574

6 [2016] 4 SCR 890 : (2016) 8 SCC 62

जाना चाहिए। तथापि, उक्त निर्णय में यह भी पाया गया है कि यदि नियुक्तिकर्ता ने आवश्यक शर्तों से विचलन करने के लिए अंतर्निहित प्राधिकार का प्रयोग किया है तो ऐसे विचलन को सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू किया जाना चाहिए। पैरा 47 और 48 में यह निम्नानुसार देखा गया था: -

> "**47**. इस चर्चा का परिणाम यह है कि बोली या बोलीदाता की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे को न केवल असफल पार्टी के दृष्टिकोण से बल्कि नियुक्तिकर्ता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। जैसा कि **रमना दयाराम शेट्टी [रमण दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,** (1979) 3 एससीसी 489] में आयोजित किया गया था, एनआईटी की शर्तों को अनावश्यक या फालतू होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक अर्थ और आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि **टाटा सेल्युलर [टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ,** (1994) 6 एससीसी 651] में बताया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम होना चाहिए। आमतौर पर, नियुक्तिकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय की ध्वनि पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। निर्णय की ध्वनि पर सवाल उठाया जा सकता है यदि यह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण है या किसी के पक्ष में इरादा है या एक निर्णय "जो कि यथोचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य करने वाला कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी नहीं पहुंच सकता था" जैसा कि **जगदीश मंडल [जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य,** (2007) 14 एससीसी 517] में आयोजित किया गया था, मिशिगन रबर **[मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2012) 8 एससीसी 216]।**
>
> **48**. इसलिए, एनआईटी की अवधि आवश्यक है या नहीं, **नियुक्तिकर्ता** द्वारा लिया गया निर्णय है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर शब्द आवश्यक है, तो नियुक्तिकर्ता के पास इससे विचलित होने का अंतर्निहित अधिकार है, बशर्ते कि विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू हो, जैसा कि **रमना दयाराम शेट्टी [रमण दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया**, (1979) 3 एससीसी 489] में आयोजित किया गया है। हालांकि, अगर नियुक्तिकर्ता द्वारा इस शब्द को सहायक या सहायक माना जाता

है, तो उस निर्णय का भी सम्मान किया जाना चाहिए। उस निर्णय की वैधता पर बहुत सीमित आधारों पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों में उल्लेख किया गया है, लेकिन निर्णय की गंभीरता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, अन्यथा यह न्यायालय निविदा जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्य को अपने हाथ में ले लेगा, जो वह नहीं कर सकता।

29. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ कि प्रश्न में परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजना है और मेगा परियोजनाओं में से एक है, यह न्यायालय विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि समझौता पहले ही प्रतिवादी बीसीसीएल और प्रतिवादी नंबर 8 के विशेष प्रयोजन वाहन के बीच किया जा चुका है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब हमने पाया है कि प्रतिवादी बीसीसीएल का आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से मनमाना, अवैध, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। जैसा कि पहले कहा गया है, सरकारी निकायों/तंत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष रूप से मेगा परियोजनाओं के लिए ठेके देने के मामले में बिल्कुल निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से कार्य करें। मनमानेपन या भेदभाव के किसी भी तत्व से पूरी परियोजना में बाधा आ सकती है जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

30 मामले के उस मद्देनजर, प्रतिवादी - बीसीसीएल के दिनांक 06.05.2024 के आक्षेपित निर्णय को अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 8 को सफल बोलीदाता घोषित किया गया। उक्त निर्णय के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई/प्रक्रिया अथवा किया गया करार भी निरस्त किया जाता है। यह प्रतिवादी-बीसीसीएल के लिए परियोजना के लिए नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने और कानून के अनुसार प्रश्नगत प्रक्रिया को संसाधित करने के लिए खुला होगा।

30. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

31. मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।